जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

चूरू

Rashtradoot

epaper.rashtradoot.com

फोनः- 256906, 256907, फैक्सः- 01562-256908 वर्षः 17 संख्याः 330 प्रभात चूरू, सोमवार 30 मार्च, 2026 पो. रजि. न. चूरू/084/2019-21 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

सऊदी अरब एयरबेस पर हमला, अमेरिकी वायुसेना का अत्याधुनिक विमान नष्ट

ईरान ने इस हमले में 6 बैलिस्टिक मिसाइल व 29 हथियारों से लैस ड्रोन का उपयोग किया

- विशेषज्ञों के अनुसार, हमला बेहद सटीक था और विमान के सबसे अहम हिस्से, रडार को निशाना बनाया गया। यह भाग विमान की मुख्य ऑपरेशनल क्षमता का केन्द्र है।

तेहरान, 29 मार्च। पश्चिम एशिया में अमेरिका, इज़रायल और ईरान के बीच जारी युद्ध अब पांचवें सप्ताह में पहुंच गया है। रविवार को सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरान की तरफ से किए गए मिसाइल और ड्रोन के बड़े हमले में अमेरिकी वायुसेना का अत्याधुनिक ई-3 ए.डब्ल्यु.एसी.एस. जासूसी विमान अवॉक्स पूरी तरह नष्ट हो गया। आईआरजीसी ने हमले की जिम्मेदारी लेते हुए दावा किया कि उसने अमेरिका के ईंधन भरने और हवाई सहायता बेड़े को निशाना बनाया, जिसमें कई बड़े सैन्य विमान नष्ट या क्षतिग्रस्त हुए। ईरान की अर्ध सरकारी समाचार संस्था तसनीम न्यूज एजेंसी ने इस्लामिक रिवोल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स (आईआरजीसी) के हवाले से यह जानकारी दी।

विश्लेषण में सामने आया है कि हमला बेहद सटीक था और विमान के सबसे अहम हिस्से रडार डोम को निशाना बनाया गया। यह वही भाग होता है जिसमें एएन/एपीवाई-2 सर्विलांस रडार सिस्टम लगा होता है, जो विमान की मुख्य ऑपरेशनल क्षमता का केंद्र है।

तस्वीरों में विमान के पिछले हिस्से में भारी संरचनात्मक क्षति देखी गई है। यह विमान हाल ही में 'ऑपरेशन एपिक फ्यूरी' के तहत इस बेस पर तैनात किया गया था और अमेरिकी वायुसेना की 552वीं एयर कंट्रोल विंग का हिस्सा था। इस घटना के बाद अमेरिकी -3 बेड़े में विमानों की संख्या 16 से घटकर 15 रह गई है।

अन्य मीडिया रिपोर्टस के अनुसार, हमले में छह बैलिस्टिक मिसाइलों और 29 हथियारों से लैस ड्रोन का इस्तेमाल किया गया।

इस हमले में कम से कम 15 अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं, जिनमें से पांच की हालत गंभीर बताई जा रही है।

आईआरजीसी ने आगे कहा कि जिस विमान को निशाना बनाया गया वह पूरी तरह से नष्ट हो गया और पास में खड़े अन्य विमानों को भी काफी नुकसान पहुंचा।

हालांकि, अमेरिकी सेंट्रल कमांड (सेंटकॉम) ने अभी तक हमले के पूरे विवरण की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार, ई-3जी सेंट्री अवाक्स विमान अमेरिकी वायु सेना का एक महत्वपूर्ण हवाई चेतावनी और युद्ध प्रबंधन प्लेटफॉर्म है, जो 250 मील से अधिक दूरी तक निगरानी करने में सक्षम होता है। इसके नष्ट होने से क्षेत्र में अमेरिकी हवाई निगरानी और कमान क्षमता पर बड़ा असर पड़ सकता है।

अमेरिका और इज़रायल ने ईरान पर संयुक्त रुप से 28 फरवरी को हमला किया था जिसमें ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला सैयद अली खामेनेई के साथ ही कई वरिष्ठ सैन्य कमांडरों और नागरिकों की मौत हो गई थी। इसके जवाब में, ईरान ने कार्रवाई करते हुए खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी और इजरायली ठिकानों को मिसाइलों और ड्रोन की लहरों से निशाना बनाया, जिससे व्यापक क्षित पहुंची है।

अमेरिका के साढ़े तीन हजार मरीन मध्य पूर्व पहुँचे

वाशिंगटन, 29 मार्च। अमेरिका के 3500 अतिरिक्त सैनिक मध्य पूर्व पहुंच चुके हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार इन सैनिकों को यूएसएस ट्रिपली जहाज से भेजा गया है। सभी सैनिक 31वीं मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट का हिस्सा हैं। उनके साथ बड़ी संख्या में लड़ाकू विमान और हथियार भी भेजे गए हैं। अमेरिका ने ईरान पर जमीनी सैन्य अभियान शुरू करने की तैयारी शुरू कर दी है।

चीन की न्यूज एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक यूएस सेंट्रल कमांड

- माना जा रहा है कि अमेरिका का यह कदम जमीनी सैन्य अभियान की तैयारी का हिस्सा है।

ने शनिवार को घोषणा की कि 3,500 मरीन और नाविकों का टास्क फोर्स शुक्रवार को मध्य पूर्व पहुंच गया है। कमांड ने एक्स पर संक्षिप्त पोस्ट में कहा, "यूएसएस त्रिपोली (एलएचए 7) पर सवार यूएस नाविक और मरीन 27 मार्च को कमांड के जिम्मेदारी वाले क्षेत्र में पहुंच गए।" पोस्ट में बताया गया कि इन सैनिकों के पास परिवहन, स्ट्राइक फाइटर विमान और एम्फीबियस असॉल्ट व टैक्टिकल संसाधन भी मौजूद हैं।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अमेरिका ने विदेशी प्रोफेशनल्स के न्यूनतम वेतन में भारी वृद्धि की

इससे विदेशी प्रोफेशनल्स को अमेरिका में नौकरी देना कंपनियों के लिए महंगा हो जाएगा तथा शायद अमेरिकी नागरिकों को ये नौकरियाँ मिल जाए

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 29 मार्च। ट्रम्प प्रशासन का एच-1 वीज़ा नियमों को कड़ा करने का नया कदम, जिसमें न्यूनतम वेतन सीमा में भारी बढ़ोतरी का प्रस्ताव है, अमेरिका की उच्च कौशल वाले प्रवासियों के प्रति नीति में बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव दर्शाता है। "सस्ते विदेशी श्रम" के उपयोग पर रोक लगाने और अमेरिकी कर्मचारियों को प्राथमिकता देने के प्रयास के रूप में पेश किए गए इस प्रस्ताव के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, खासकर उन भारतीय पेशेवरों के लिए जो एच-1 बी व्यवस्था में बड़ी संख्या में शामिल हैं।

इस प्रस्ताव का मुख्य बिंदु यह है कि नियोक्ताओं (एम्पलॉयर्स) को एच-1बी वीज़ा धारकों को दिए जाने वाले वेतन में बड़ी बढ़ोतरी करनी होगी। वेतन की न्यूनतम सीमा बढ़ाकर सरकार कंपनियों के लिए विदेशी कर्मचारियों को रखने को महंगा बनाना चाहती है, ताकि वे घरेलू कर्मचारियों को प्राथमिकता दें। सिद्धांत रूप में यह ट्रम्प काल की संरक्षणवादी नीतियों के अनुरूप है। हालांकि, व्यवहार में यह कदम उस संतुलित वैश्विक प्रतिभा व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है,

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- इस नई नीति का सबसे ज्यादा असर भारतीय मूल के इंजीनियर, आई.टी. वर्कर्स पर पड़ेगा, क्योंकि एच-1बी वीज़ा के मार्फत अमेरिका में लगभग 2.8 लाख भारतीय काम कर रहे हैं। पर, अब भारतीय इंजीनियर्स आदि का अमेरिका में काम करने का रास्ता और सकड़ा हो जाएगा।
- इसका भारत को एक लाभ तो है कि अब ये प्रोफेशनल्स, भारत लौटने को मजबूर हो जाएंगे तथा भारत के लोकल "टैलेन्ट पूल" को मजबूती मिलेगी तथा स्टार्टअप, वित्तीय टैक्नॉलजी व डिजिटल सर्विसेज़ सैक्टर को लाभ पहुँचेगा।
- पर, दूसरी ओर एक तत्कालिक नुकसान भी है। भारतीय प्रोफेशनल्स द्वारा, भारत को भेजे जा रहे "रैमिटैंस" (वेतन आदि) में काफी कमी आएगी, क्योंकि नौकरी जाने के बाद काफी भारतीय प्रोफेशनल्स भारत लौटने को होंगे।

यूएई व बहरीन में दो बड़ी फैक्ट्रियों को ईरान ने निशाना बनाया

ये दोनों फैक्ट्री अमेरिकी सैन्य व एयरोस्पेस उद्योग के लिए महत्वपूर्ण उत्पादन करती थीं

- यूएई की ईमाल फैक्ट्री विश्व की सबसे बड़ी एल्युमीनियम उत्पादन लाइन है तथा बहरीन की अल्बा फैक्ट्री में अमेरिकी कंपनियों का निवेश व हिस्सेदारी भी है।

तेहरान, 29 मार्च। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स (आईआरजीसी) ने दावा किया है कि उसने फारस की खाड़ी स्थित संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन में अमेरिकी सैन्य और एयरोस्पेस उद्योगों से जुड़ी दो औद्योगिक फैक्ट्रियों को निशाना बनाया।

आईआरजीसी के अनुसार यह कार्रवाई अमेरिका-इज़रायल की ओर से किए गए हमले के जवाब में की गई है जिसमें मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। ईरान की अर्ध सरकारी समाचार संस्था तसनीम न्यूज एजेंसी ने आईआरजीसी के हवाले से उक्त जानकारी दी।

आईआरजीसी ने एक बयान में कहा कि फ़ारस की खाड़ी के दक्षिणी तटीय राज्यों के औद्योगिक बुनियादी ढ ांचे को निशाना बनाने के अमेरिका और इज़रायल के दुर्भावनापूर्ण कार्यों के बाद आईआरजीसी एयरोस्पेस फ़ोर्स और नौसेना के लड़ाकों ने एक हाइब्रिड और लक्षित अभियान चलाया। उन्होंने इस क्षेत्र में अमेरिका के सैन्य और एयरोस्पेस उद्योगों से जुड़ी दो फैक्ट्रियों- यूएई में एमिरेट्स एल्युमीनियम (ईमाल) फैक्ट्री और बहरीन में एल्युमीनियम बहरीन (अल्बा) फैक्ट्री को निशाना बनाया है।

ईमाल फैक्ट्री में दुनिया की सबसे लंबी एल्युमीनियम उत्पादन लाइन है, जिसकी उत्पादन क्षमता 1.3 मिलियन टन है। वहीं, अल्बा एल्युमीनियम फैक्ट्री में अमेरिकी कंपनियों का निवेश और हिस्सेदारी है जो अमेरिका के सैन्य उद्योगों के लिए सामान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

केन्द्र सरकार ने केरोसिन की सप्लाई में भी ढील दी

नई दिल्ली, 29 मार्च। होर्मुज संकट और वैश्विक तनाव के बीच भारत सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। रॉयटर्स की जानकारी के अनुसार, भारत सरकार ने केरोसिन यानी मिट्टी के तेल

- ऊर्जा संकट के बीच इस कदम से आम आदमी को राहत मिलेगी।

की सप्लाई आसान बनाने के लिए नियमों में ढील दी है। इसका मकसद है कि जिन इलाकों में गैस या बिजली की कमी है, वहां लोगों को खाना बनाने और रोशनी के लिए तुरंत केरोसिन मिल सके।

सरकार ने साफ किया है कि पेट्रोलियम सुरक्षा और लाइसेंस से जुड़े कुछ नियमों को अस्थायी तौर पर आसान किया गया है। इससे 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जरूरत के हिसाब से केरोसिन की सप्लाई की जा सकेगी।

सरकार का कहना है कि इस कदम से आम लोगों को सीधा फायदा होगा। खासकर ग्रामीण और दूर-दराज के इलाकों में जहां अभी भी लोग केरोसिन पर निर्भर हैं। सरकार ने कहा कि जरूरत पड़ने पर तुरंत केरोसिन उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि किसी को खाना बनाने या रोशनी के लिए परेशानी न हो। यह फैसला अस्थायी है, लेकिन हालात सामान्य होने तक इसे जारी रखा जाएगा।

अमेरिका के सभी 50 राज्यों में ट्रंप के खिलाफ रैलियां निकलीं

वॉशिंगटन डीसी, 29 मार्च। ईरान युद्ध और राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की कार्रवाइयों के विरोध में शनिवार को अमेरिका के सभी 50 राज्यों और यूरोप के कई हिस्सों में "नो किंग्स" रैलियों में भारी भीड़ सड़कों पर उतर आई। बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक, लोग

- "नो किंग्स" रैली में 80 लाख से अधिक लोगों ने ईरान युद्ध के खिलाफ प्रदर्शन किया।

कई मुद्दों पर अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए इकट्ठा हुए।

'नो किंग्स रैली' में 80 लाख लोगों ने हिस्सा लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पूरे अमेरिका के सभी 50 राज्यों में 3,300 से ज्यादा स्थानों पर ये प्रदर्शन आयोजित किए गए।

आयोजकों ने बताया कि अक्टूबर में हुए पिछले नो किंग्स प्रदर्शनों की तुलना में इस बार करीब 10 लाख ज्यादा लोग शामिल हुए और लगभग 600 ज्यादा कार्यक्रम आयोजित किए गए।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

यूक्रेन के हमलों ने रूस का तेल निर्यात 40 प्रतिशत गिराया

रूस के उस्त-लूगा बंदरगाह का एक तेल लोडिंग पियर ड्रोन हमलों में पूरी तरह नष्ट हो गया

- रूस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल निर्यातक है। तेल उत्पादन उसके राष्ट्रीय बजट में कमाई के मुख्य स्रोतों में है। इस समय जब तेल 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर है, रूस को बहुत हानि हो रही है।

मॉस्को/कीव, 29 मार्च। यूक्रेन द्वारा लगातार किए जा रहे ड्रोन हमलों ने रूस के तेल निर्यात ढ ांचे को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यूक्रेन के ड्रोन हमले तथा एक प्रमुख पाइपलाइन पर हमला और टैंकरों को जब्त किए जाने के बाद रूस की तेल निर्यात क्षमता का कम से कम 40 फीसदी हिस्सा ठप पड़ गया है।

रूस के प्रमुख तेल निर्यात केंद्र उस्त-लूगा बंदरगाह पर हुए ड्रोन हमले में कम से कम एक तेल लोडिंग पियर पूरी तरह नष्ट हो गया है, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुआ है। सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर आई रिपोर्ट्स में यह जानकारी सामने आई है।

अंतरराष्ट्रीय मीडया एनबीसी व अन्य रिपोर्ट के अनुसार, पेट्रोलियम उत्पादों के रिसाव के कारण लगी आग और हमले में न केवल बर्थ बल्कि कई स्टोरेज टैंक और तकनीकी ढ ांचे भी प्रभावित हुए हैं। इससे पहले, 23 मार्च की रात को यूक्रेन ने रूस के बड़े तेल बंदरगाह प्रिमोर्स्क पर हमला किया था, जिसमें भीषण आग लग गई थी। इस आग में कई बर्थ और दो टैंकर चपेट में आ गए थे। इसके बाद 25 मार्च और फिर 27 मार्च की रात को यूक्रेनी ड्रोनों ने उस्त-लूगा और प्रिमोर्स्क बंदरगाहों को दोबारा निशाना बनाया। ये दोनों बंदरगाह बाल्टिक सागर क्षेत्र में रूस के सबसे अहम तेल निर्यात केंद्र माने जाते हैं।

यह शटडाउन रूस के तेल सप्लाई में अब तक की सबसे बड़ी रुकावट है। रूस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल एक्सपोर्टर है और यह रुकावट मॉस्को के लिए ठीक ऐसे समय पर आई है जब ईरान युद्ध के कारण तेल की कीमतें 100 प्रति बैरल से ऊपर चली गई हैं। रूस का तेल उत्पादन राष्ट्रीय बजट के लिए कमाई के मुख्य स्रोतों में से एक है और 2.6 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज़रूरी है।

इस महीने यूक्रेन ने रूस के तेल और ईंधन एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर ड्रोन हमलों को तेज कर दिया है। इन हमलों में रूस के तीन मुख्य पश्चिमी तेल एक्सपोर्ट पोर्ट्स को निशाना बनाया गया, जिनमें ब्लैक सी पर नोवोरोस्सिएस्क, और बाल्टिक सी पर प्रिमोर्स्क और उस्त-लुगा शामिल हैं।

छत्तीसगढ़ में 5 लाख का ईनामी नक्सली कमांडर मारा गया

सुकमा, 29 मार्च। सुकमा जिले के पोलमपल्ली थाना क्षेत्र के जंगलों में रविवार सुबह पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता मिली है। मुठभेड़ में 5 लाख का इनामी नक्सली कमांडर मारा गया है।

सुकमा के एसपी किरण चव्हाण ने बताया कि माओवादियों की मौजूदगी की सूचना पर डीआरजी (डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड) की टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। इसी दौरान जंगल-पहाड़ी क्षेत्र में जवानों और नक्सलियों

- सुकमा के जंगलों में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में पुलिस को यह सफलता मिली।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

स्टेनोग्राफर भर्ती में कर्मचारी चयन बोर्ड की अतिरिक्त रियायत खारिज

हाईकोर्ट ने कहा कि, 444 पदों की इस भर्ती के लिए कर्मचारी चयन आयोग 45 दिनों में नई मैरिट लिस्ट बनाए

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर, 29 मार्च। राजस्थान हाईकोर्ट में स्टेनोग्राफर एंड पर्सनल असिस्टेंट ग्रेड-2 भर्ती के दूसरे फेज के दौरान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा अभ्यर्थियों को गलतियों में 5 प्रतिशत की अतिरिक्त राहत देने के फैसले को चुनौती दी गई। सचिवालय के लिए 444 पदों की इस भर्ती की विज्ञप्ति 26 फरवरी 2024 को जारी हुई थी, जिसकी मैरिट लिस्ट 25 सितंबर 2025 को जारी की गई थी।

अदालत ने इस भर्ती को लेकर दायर की गई 40 याचिकाओं को एक साथ सुनवाई की। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता संदीप पाठक ने अदालत को बताया कि, इस भर्ती की चयन प्रक्रिया को दो भागों में बांटा गया था। प्रथम चरण में कई तरह के लिखित परीक्षाएं थी, जबकि दूसरे चरण में स्टेनोग्राफी टेस्ट था। प्रथम चरण में हर अभ्यर्थी को 40 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण करना था, तभी वह दूसरे चरण के लिए पात्र माना जाएगा।

उन्होंने आगे बताया कि, प्रथम चरण की परीक्षाएं 5 अक्टूबर 2024 को आयोजित की गई थी, जिसका परिणाम 23 दिसंबर को जारी किया गया था। दूसरे चरण में स्टेनोग्राफी टेस्ट के बाद मैरिट सूची 25 सितंबर 2025 को जारी की गई थी, जिसमें 904 अभ्यर्थियों को पात्र माना गया। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि, कर्मचारी चयन बोर्ड और राज्य सरकार ने गैरकानूनी ढंग से अभ्यर्थियों को फेज-2 में 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत अतिरिक्त गलतियों व त्रुटियों पर राहत दी, जबकि नियमानुसार गलतियों में राहत केवल सामान्य वर्ग में 20 प्रतिशत तथा एससी-एसटी वर्ग को 25 प्रतिशत दी जाती है। उन्होने कहा कि, 5 प्रतिशत अतिरिक्त राहत का प्रावधान तभी लागू किया जाता है, जब भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों की संख्या तय वैकेंसी से कम रहे।

- अदालत ने सवाल उठाया कि, जब 5 प्रतिशत की अतिरिक्त राहत दिए बिना भी 643 अभ्यर्थी पात्र थे, फिर इनमें से 444 पद क्यों नहीं भरे गए?
- याचिकाकर्ताओं का कहना है कि 904 अभ्यर्थियों ने मैरिट लिस्ट में स्थान पाया है, कर्मचारी चयन बोर्ड ने 5 प्रतिशत की अतिरिक्त राहत गैरकानूनी तरीके से दी है।

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि 904 अभ्यर्थियों में से 643 अभ्यर्थी ने बिना 5 प्रतिशत की अतिरिक्त राहत के फेज-2 की परीक्षाएं उतीर्ण कर ली थी, परंतु यह राहत देकर अभ्यर्थियों की सूची गैरकानूनी तरीके से बढाई गई है।

हाईकोर्ट के न्यायाधीश आनंद शर्मा ने तमाम तथ्यों को सुनने के बाद अपने आदेश में कहा कि, उनके समक्ष प्रस्तुत रिकॉर्ड से साफ जाहिर होता है कि कर्मचारी चयन बोर्ड के पास 5 प्रतिशत की अतिरिक्त राहत दिए बिना भी 643 अभ्यर्थी थे, जिनमें से उन्हें केवल 444 पद भरने थे। प्राप्त दस्तावेजों से जाहिर होता है कि सामान्य तथा अन्य सभी आरक्षित वर्गों में उपयुक्त संख्या में अभ्यर्थी थे, जिनमें से रिक्त पदों की भर्ती की जा सकती थी। ऐसे में अतिरिक्त राहत देने का कोई औचित्य नहीं था।

अदालत ने कहा कि, अगर चयन बोर्ड कोई वैटिंग लिस्ट भी बनाना चाहता था तो वह सूची भी इन 643 अभ्यर्थियों में से ही बनाई जा सकती थी। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रस्तुत तर्कों को स्वीकारते हुए कहा कि, 25 सितंबर और 21 अक्टूबर 2025 को जारी मैरिट लिस्ट तथा अंतरिम मैरिट सूची को खारिज किया जाता है। उन्होंने आदेश दिए कि अब कर्मचारी चयन बोर्ड 45 दिनों में नई मैरिट सूची बनाए, जिन्हें 5 प्रतिशत की अतिरिक्त रियायत का फायदा नहीं दिया गया है।

हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों में बर्फ गिरी

शिमला, 29 मार्च। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में ताज़ा बर्फबारी और राज्यभर में रविवार को हुई व्यापक बारिश ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया। ठंड एक बार फिर बढ़ गई है। लाहौल-स्पीति जिला

- बर्फ और बरसात ने सड़कों पर फिसलन बढ़ाई, रोहतांग दर्रा आंशिक रुप से बंद।

प्रशासन ने यात्रियों को फिसलन भरी सड़कों पर सावधानी से वाहन चलाने की सलाह जारी की है।

जिला आपात रिपोर्ट के अनुसार कई ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बर्फबारी के कारण रास्ते बंद हो गए हैं। रोहतांग दर्रा और कुंजुम दर्रा सहित प्रमुख मार्गों पर आवाजाही ठप है। रोहतांग मार्ग के आंशिक रूप से बंद होने

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)